इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2017—माघ 14, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 3rd January 2017

No.E-29-II-15-18-2005.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005, and as approved vide Resolution dated 21 October 2016 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh (Competent Authority',) hereby makes following amendments in the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006, which were published in the Madhya Pradesh Gazette Extra Ordinary dated 4th of March, 2006:—

(i) In Rule 3 subrule 1 after 'B'.—

"Application can also be made online through the website of Madhya Pradesh High Court.

The acknowledgment of such online application be provided online & by SMS" is added.

(ii) In Rule 4 subrule (1) after after application.—

"The application received online may be transferred to another Public Authority by Online/Offline mode as the case may be" is added.

(iii) In Rule 4 subrule (2) after refunded.—

"Provided that in case of online application, Rejection Order may be issued online" is added.

(iv) In Rule 4 subrule (3) after thereof.—

"The information may be supplied online wherever possible" is added.

(v) In Rule 4 subrule (4) after authorized person.—

"In case of Online application, the information may be supplied online wherever possible" is added.

(vi) In Rule 5 subrule (1)(b) after appellate authority.—

"An appeal before the appellate Authority may be presented online" is added.

(vii) In Rule 7 subrule (1) after Treasury Challan.—

"(including Cyber Treasury Challan) and after Treasury Head **"0070 Other Administrative Services or payment through Online portal (www.mphc.gov.in/e-rti) under the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006"** is added.

(viii) In Rule 7 subrule (2) after Treasury Challan.—

"(including Cyber Treasury Challan) and after Treasury Head **"0070 Other Administrative Services or payment through Online portal (www.mphc.gov.in/e-rti) under the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006" is added.**

(ix) In Form A & F after Treasury Challan.—

"Cyber Treasury Challan" is added.

By order of Hon'ble the Chief Justice
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र. 37-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, महोदय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तंभ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**श्री ओंकार नाथ,** विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, गुना.	गुना	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, जबलपुर की हैसियत से.